अध्यक्षीय शोध कदम (SRI) ने स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सतत विकास लक्ष्य के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की

नई दिल्ली, 28 मार्च 2017 : अध्यक्षीय शोध कदम (SRI) ने आज संसदीय ज्ञानपीठ में स्वास्थ्य सतत विकास लक्ष्य (SDGs) के बारे में संसद सदस्यों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की पूर्व सचिव सुश्री के. सुजाता राव और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. ए.के.पांडा ने कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया।

डॉ. पांडा ने अपने प्रस्तुतीकरण में कहां की SDGs अपने क्षेत्र और महत्व की दृष्टि से अद्वितीय हैं और ये सतत विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्तम्भ हैं । SDGs को समेकित और सार्वभौमिक बताते हुए उन्होंने कहां कि ये केवल विकासशील ही नहीं अपितु सभी देशों पर लागू होते हैं । उन्होंने इस बात पर बल दिया की SDGs का प्रयोजन यह ह कि कोई भी पीछे न रह पाये और इनमें समानता और वंचित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर अत्यधिक बल दिया गया ह।

यह उल्लेख करते हुए कि स्वास्थ्य अन्य अनेक SDGs और उससे संबंधित उद्देश्यों से जुड़ा हुआ हैं, डॉ. पांडा ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण कई अन्य लक्ष्यों से संबंधित हमारी रणनीतियों को प्रभावित करते ह। इन लक्ष्यों का प्रयास सभी को संरक्षण प्रदान करना ; बचपन का विकास, देखभाल और प्री-प्राइमरी शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना और सभी महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली सभी प्रकार की हिंसा हो समाप्त करना हैं । डॉ. पांडा ने यह भी कहा कि अच्छा स्वास्थ्य साफ और सस्ते पानी तक सभी की समान रूप से पहुँच सुनिश्चित करने ; कुपोषण को समाप्त करने और सभी प्रकार की हिंसा तथा उससे संबंधित मृत्यु दर को कम करने के लिए भी जरूरी ह।

कार्यशाला में बोलते हुए सुश्री सुजाता के.राव ने इस बात पर बल दिया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में SDGs से संबंधित प्रमुख मुद्दों में अंतर क्षेत्रीय कंवर्जेंस ; असमानता और विषमताएं ; आवश्यक देखभाल के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज ; देखभाल लागत और विनयामक ढांचों का निर्माण

शामिल हैं । मानव विकास इंडेक्स में भारत की स्थिति के बारे में सुश्री राव ने कहा कि 194 देशों में भारत का 131वां स्थान ह□और असमानता से संबंधित इंडेक्स में 135वां स्थान ह□। इस संदर्भ में, नेतृत्व और बेहतर शासन प्रदान करने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने की संसद सदस्यों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती ह□।